Naval Officers are permitted to seek premature retirement on the following grounds :—

(i) Supersession

(ii) Compassionate reasons

(iii) Permanent Low Medical Category

(iv) Absorption in the Public Sector/Resettlement in civil life within a period of 2 years from the date of normal retirement.

All cases of premature retirement are approved by the Govt. on the recommendations of the Chief of Naval Staff subject to their fulfilling the laid down guidelines/criteria and after keeping the Navy's manpower requirements in mind.

The number of officers of the ranks of Commodores/Captains and Commanders who proceeded on premature retirement during 1989-90 and 1990-91 is as follows :—

Year	Commodores/ Captains	Commanders
1989-90 . . .	9	33
1990-91 . . .	19	98

News Item 'Chinese Naval Modernisation Plan'

1188. SHRI DHULESHWAR MEENA : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item which appeared in "The Observer of Business and Politics" New Delhi dated the 13th April, 1992 captioned "Chinese naval modernisation plan alarm defence experts" ; and

(b) if so, what is Government's reaction thereto particularly in the context of being a major determinant in India's security calculas, according to the Indian Defence analysis ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI S. KRISHNA KUMAR) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government remain alert to all developments that have a bearing on the national security, including the modernisation programmes of the Defence forces of neighbouring countries. The Indian Navy remain prepared to meet threats to India's security and her maritime interests.

Corruption charges against Chairman-cum-Managing Director of BEML

1189. SHRI RAM AWADHESH SINGH : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chairman-cum-Managing Director of Bharat Earth Movers Limited has acquired wealth disproportionate to his known sources of income, in awarding contracts to known persons ignoring the interests of the Public Exchequer ;

(b) whether Government propose to hold an enquiry by CBI into all the purchases made and contracts awarded ; and

(c) if so, by when and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI S. KRISHNA KUMAR) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

1190. [*Transferred to the 11th May, 1992*]

रोहतांग दर्रे पर सुरंग

1191. **श्री महेश्वरी सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे पर एक सुरंग का निर्माण-कार्य शुरु हो गया है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब शुरु किया गया; और

(ग) निर्माण-कार्य की अद्यतन स्थिति क्या है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री एस० कृष्ण कुमार):

(क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राजपूताना राइफल्स के पास से "झांसी की रानी" के झंडे का गुम हो जाना

1192. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजपूताना राईफल्स की सुरक्षा में रखा गया झांसी की रानी का झंडा रहस्यमय ढंग से गुम हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री एस० कृष्ण कुमार): (क) और (ख) झांसी की रानी का झंडा जिसे 1857 में कब्जे में लिए जाने का दावा किया गया था, 5 राजपूताना राइफल्स के पास था। इस झंडे को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इसे अक्तूबर, 1977 में राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर, दिल्ली छावनी में भेज दिया गया क्योंकि इस बटालियन को युद्धक्षेत्र में जाना था। 1980 में यूनिट द्वारा झंडा वापस लेने की मांग किए जाने पर वह नहीं मिल पाया।

1980 में यूनिट की एक जांच अदालत और 1982 में एक स्टाफ जांच अदालत बिठाई गई परन्तु वह झंडे का पता नहीं लगा सकी हालांकि इसमें कतिपय अफसरों द्वारा की गई चूकों का उल्लेख किया गया था। तद्नुसार, सेनाध्यक्ष द्वारा मामला बंद कर दिया गया। बाद में सरकार ने मामले की समीक्षा की और उसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया। ब्यूरो ने 1988 में मामला दर्ज किया और उसकी व्यापक जांच की। इंटरपोल तथा विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों, विशेषकर ब्रिटेन स्थित दूतावास के माध्यम से भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पूछताछ की गई परन्तु झंडे के बारे में कोई प्रमाण या सुराग नहीं मिला। परिणामतः केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मामला बंद कर दिया और आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 173 के अंतर्गत मामला बंद करने के लिए चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिल्ली की अदालत में रिपोर्ट दर्ज की। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा झंडे का पता नहीं लगाया जा सका या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं बनाया जा सका इसलिए 1991 में सरकार के पास मामले को बंद करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहा गया था।

Unauthorised Water connections in Kanpur Cantonment Board

1193. SHRI GHUFRAN AZAM : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether the lapses of Kanpur Cantonment Board in checking and preventing the menace of unauthorised water connections have been causing huge loss of revenue to the Board ;

(b) whether the Kanpur Cantonment Board has been neglecting to recover proper rates and taxes from the residents in order to increase the quantum of Grant-in-Aid from the Central Government ;

(c) whether unauthorised building constructions are also gaining support from a section of the employees of the Board ; and

(d) what immediate steps are to be taken for checking of such lapses ?